सिविल विविध

न्यायमूर्ति *डी. के. महाजन और पी. सी. जैन*, के समक्ष

हरबंस लाल सूरी - *याचिकाकर्ता*

***बनाम***

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता

**1968 की सिविल रिट संख्या 1266**

17 जुलाई, 1968

***पंजाब*** *आबकारी अधीनस्थ सेवा नियम,* 1943 - *नियम* 7 (1) (< ■) (») - *वाक्यांश ' 'सीधी नियुक्ति' - विधियों की व्याख्या - नियमों के सेट की व्याख्या - घंटे किए जाने का समय।*

*पंजाब* आबकारी अधीनस्थ सेवा नियम, 1943 के नियम 7 (1) (सी) (ii) में, 'सीधी नियुक्ति' वाक्यांश का उपयोग केवल सरकारी सेवा में नहीं रहने वाले व्यक्तियों और सरकारी सेवा में व्यक्तियों के बीच अंतर करने के लिए किया गया है। 'सीधी नियुक्ति' वाक्यांश का उपयोग आगे इस बात पर प्रकाश डालता है कि सेवा में सभी नियुक्तियां सीधी नियुक्तियां हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भर्ती किस **स्रोत** से ली गई है।

(पैरा 6)

है कि यह निर्माण का एक मौलिक नियम है कि नियमों के एक सेट की व्याख्या करते समय, उन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप से एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें असंगत नहीं बनाया जाना चाहिए।

(पैरा 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 के 21 मार्च, 1968 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता को कराधान निरीक्षक के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस वाश और अधिवक्ता बी एस वासु। हरियाणा के एडवोकेट जनरल आनंद सरूप प्रतिवादियों की ओर से।

**आदेश**

न्यायमूर्ति *डी. के* महाजन,- याचिकाकर्ता के विद्वान वकील एम. आर. एच. एस. वासू द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि विवाद के अलावा, जिस पर बाद में ध्यान दिया जाएगा, उनकी याचिका में अन्य विवाद 1967 के सिविल रिट नंबर 2485 में हमारे फैसले से समाप्त होते हैं।

2.श्री वासु का अतिरिक्त तर्क यह है कि याचिकाकर्ता सीधी भर्ती नहीं है। उन्हें एक अन्य सरकारी विभाग से स्थानांतरण द्वारा उप-निरीक्षक नियुक्त किया गया था जिसमें वह सेवारत थे। विद्वान वकील के अनुसार, नियम 8 (3) (iii) केवल सीधी भर्ती पर लागू होता है और चूंकि वह सीधी भर्ती नहीं है, इसलिए उस नियम के तहत उपनिरीक्षक के रूप में उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है, और इसलिए, उसकी समाप्ति और उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तन कानूनी नहीं है।

**3. विद्वान वकील के तर्क की सराहना करने के लिए, नियम 5, 7 और 8 को एक साथ निर्धारित करना उचित होगा: –**

**उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता**

**एस>। किसी भी व्यक्ति को सेवा में सीधे नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की इंटरमीडिएट परीक्षा (कला या विज्ञान में) या वरिष्ठ ऑक्सफोर्ड या वरिष्ठ कैम्ब्रिज स्थानीय, परीक्षा, या एचिसन कॉलेज, लाहौर की डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो ।**

**परन्तु आबकारी और कराधान आयुक्त, लिखित में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से, किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जिसके पास इस नियम द्वारा निर्धारित अर्हताएं नहीं हैं।**

**भर्ती की विधि**

**7. (1) सेवा में पद भरे जाएंगे-**

**1. निरीक्षकों के मामले में-**

**1. उप-निरीक्षकों के बीच से नियुक्ति द्वारा।**

**2. सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा;**

**1. उप-निरीक्षक स्केल के मामले में-**

**1. उप-निरीक्षकों के बीच से नियुक्ति द्वारा रिजर्व छोड़ दें; नहीं तो**

**1. सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।**

**1. उप-निरीक्षकों के मामले में रिजर्व छोड़ दें-**

**1. सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर**

**स्थानांतरण द्वारा; नहीं तो**

2. **उन व्यक्तियों की सीधी नियुक्ति द्वारा जो पहले से ही सरकारी (पेंशन योग्य) सेवा में नहीं हैं।**

**2.जब सेवा में कोई रिक्ति होती है, या होने वाली होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह निर्धारित करेगा कि ऐसी रिक्ति को किस तरीके से भरा जाएगा।**

**3.पदोन्नति द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति सख्ती से चयन द्वारा की जाएगी और ऐसी किसी भी नियुक्ति को किसी भी व्यक्ति को पदोन्नति से इनकार करने के रूप में नहीं माना जाएगा।**

**4.सेवा में कोई भी पद पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति से नहीं भरा जाएगा, जब तक कि संबंधित कार्यालय के प्रमुख ने कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अपने मूल पद पर अपने ग्रहणाधिकार को बनाए रखने और प्रत्यावर्तित होने पर उसे वापस लेने के लिए लिखित रूप में सहमति नहीं दी है।**

**(8) (1)** सेवा के किसी भी सदस्य को परिशिष्ट क में विनिर्दिष्ट किसी भी पद पर (आबकारी उप-निरीक्षक (समय-वेतनमान) के पद को छोड़कर) तब तक प्रतिरक्षित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किए गए सदस्यों के मामले में दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर उस पद पर सेवा नहीं दी हो, या अन्यथा भर्ती किए गए सदस्यों के मामले में एक वर्ष की सेवा न की हो।

***स्पष्टीकरण-*** **निरंतर कार्यवाहक सेवा को परिवीक्षा पर खर्च की गई अवधि के रूप में माना जाएगा, लेकिन किसी भी सदस्य को परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर स्थायी रिक्ति के अलावा किसी अन्य तरीके से पुष्टि नहीं की जाएगी।**

**2.यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी सदस्य का कार्य या आचरण, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है यदि उसे सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किया गया है, या यदि उसे भर्ती किया गया है तो उसे उसके पूर्व पद पर वापस कर सकता है।**

**3.किसी सदस्य की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे सदस्य को पूर्वव्यापी प्रभाव से मूल रूप से नियुक्त कर सकता है, यदि कोई रिक्ति मौजूद है, या, यदि उसका कार्य या आचरण, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं रहा है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है यदि उसे सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किया गया है, या उसे उसके पूर्व पद पर वापस कर दिया जाए यदि उसे सीधी नियुक्ति के अलावा अन्यथा भर्ती किया गया है, या परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो परिवीक्षा की पहली अवधि की समाप्ति पर पारित हो सकता है-**

1. **बशर्ते कि विस्तार सहित परिवीक्षा की कुल अवधि, यदि कोई हो, सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों के मामले में तीन वर्ष से अधिक नहीं**

होगी, और अन्यथा भर्ती किए गए व्यक्तियों के मामले में दो वर्ष;

1. बशर्ते कि, केवल किसी विशेष कारणों से दी जाने वाली आबकारी और कराधान आयुक्त की मंजूरी के बिना, किसी भी व्यक्ति को मूल उप-निरीक्षक समय-मान या अवकाश रिजर्व नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है;

1. बशर्ते कि सेवा में सीधे नियुक्त किसी भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नहीं रखा जाएगा, जब तक कि वह अपनी नियुक्ति की तारीख से निरंतर कार्यवाहक या मूल सेवा के तीन साल के भीतर आबकारी उप-निरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है।

* * * * *

4.श्री वासु का तर्क है कि सीधे भर्ती किया गया व्यक्ति नियम 7 (एल) (सी) (ii) में उल्लिखित है और केवल भर्ती की इस श्रेणी के लिए, नियम 8 (3) (iii) लागू होता है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि नियम 5 में शैक्षिक योग्यता केवल सीधी भर्ती के लिए प्रदान की जाती है और
वे उन लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं जो अन्य सरकारी विभागों से स्थानांतरण पर आते हैं।

5.दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप का तर्क है कि नियम 7 के तहत सेवा में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति सीधी भर्ती हैं और नियम 7 (1) (सी) में एक अंतर आवश्यक था क्योंकि नियुक्ति उप-निरीक्षकों (लीव रिजर्व) के लिए थी, और यह केवल उप-निरीक्षकों (अवकाश रिजर्व) के मामले में है कि सीधी भर्ती के लिए प्रावधान किया गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निरीक्षकों या उप-निरीक्षकों के मामले में कोई सीधी भर्ती नहीं हो सकती है। वह आगे बताते हैं कि हालांकि पदोन्नति द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण कोटा तय नहीं है। जहां भी व्यक्तियों को पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उनके लिए हमेशा एक आरक्षण कोटा तय किया जाता है। आगे इस बात पर जोर दिया जाता है कि यदि श्री वासु द्वारा की गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो नियम 5 निरर्थक हो जाएगा क्योंकि यह केवल सेवा में प्रवेश करने वालों के एक बहुत ही सीमित वर्ग पर लागू होगा और नियमों के निर्माताओं का यह इरादा नहीं हो सकता है कि व्यक्तियों को नियम 5 में निर्धारित योग्यता के बिना सेवा में प्रवेश करना चाहिए।

6.संबंधित दलीलों के सापेक्ष गुण-दोष के बीच ही मामले का निपटारा किया जाना है। वास्तव में, नियम 7 (1) (सी) (; ii) में, 'सीधी नियुक्ति' वाक्यांश का उपयोग केवल सरकारी सेवा में नहीं रहने वाले व्यक्तियों और सरकारी सेवा में व्यक्तियों के बीच अंतर करने के लिए किया गया है। 'सीधी नियुक्ति' वाक्यांश का उपयोग आगे इस बात पर प्रकाश डालता है कि सेवा में सभी नियुक्तियां सीधी नियुक्तियां हैं और ऐसा प्रतीत होता है, यदि नियम 5 का संदर्भ दिया जाता है, जहां फिर से 'सीधी नियुक्ति' वाक्यांश का उपयोग किया जाता है या, उदाहरण के लिए, 'सीधे नियुक्त' किया जाता है। नियम 8 (3) (iii) में भी यही वाक्यांश

**आता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री आनन्द स्वरूप का यह तर्क ठोस है कि नियम 7 के अंतर्गत सभी नियुक्तियां सीधी नियुक्तियां हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भर्ती किस स्रोत से ली गई है। यह निर्माण का एक मौलिक नियम है कि नियमों के एक सेट की व्याख्या करते समय, उन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप से एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए, न कि उन्हें असंगत बनाने के लिए। इसलिए, मैं श्री वासु के तर्क से सहमत नहीं हूं और मुझे इसे वापस लेना चाहिए।**

7. कोई **अन्य विवाद नहीं दिया गया है।** ऊपर दर्ज कारणों के लिए, यह याचिका विफल हो जाती है और लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**जोगिंद्र जांगड़ा**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**हथीन, हरियाणा**